Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 20-03-2007

Participants : Singh Dr. Raghuvansh Prasad

an>

Title: The Minister of Rural Development made a statement regarding status of implementation of components of Bharat Nirman relating to Ministry of Rural Development.

ग्रामीण विकास मंत्री (डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित भारत निर्माण घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं,

* भारत के माननीय राट्रपति जी ने 25 फरवरी, 2005 को संसद को सम्बोधित अपने भााण में ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के लिए एक प्रमुख योजना की घोाणा की थी जिसे अब चार वर्ों अर्थात् 2005-2009 की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली " भारत निर्माण " नामक व्यवसायिक योजना के रूप में स्वीकार किया गया है । ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत निर्माण के छह घटकों में से तीन घटकों अर्थात् ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को कार्यान्वित कर रहा है । हालांकि उ पर्युक्त तीन घटकों की कार्यसूची के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी दी जाती है, फिर भी भारत निर्माण के अंतर्गत विशेा पैकेज से कार्यक्रम को समयबद्ध, पारदर्शी तथा जवाहदेह बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है । मैं इस महान सदन को इन तीनों घटकों के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति के बारे में बताना चाहूंगा ।

ग्रामीण सड़कें

ग्रामीण सड़क संपर्कता को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था । " भारत निर्माण " के ग्रामीण सड़क घटक का लक्ष्य 1000 तथा इससे अधिक की आबादी (पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 500) वाली सभी बसा वटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है । तद्नुसार, 66802 बसावटों को थ्रूरूटों के माध्यम से 1.94 लाख कि0मी0 लंबी सड़कों की मरम्मत करने के अलावा, 1.46 लाख कि0मी0 लम्बाई वाली नई सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है । भारत निर्माण के पहले दो वर्ों के दौरान प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों से यह पता चला है कि 10303 बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है , 32590 लाख कि0मी0 लम्बाई वाली नई सड़कें बन चुकी हैं तथा 36341 लाख कि0मी0 लम्बाई वाली थ्रूरूटों का उन्नयन हो चुका है तथा इस पर 2005-06 के

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6168/07

दौरान 4219.98 करोड़ रू0 और 2006-07 के दौरान 5376.28 करोड़ रू0 खर्च हुए हैं। ग्रामीण सड़कों के लिए बजट 2007-08 में 11000 करोड़ रू0 के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है ।

सरकार ने निर्माण कार्य की उचित गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली बनाई है । जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य-स्थलों पर लगाए गए जन सूचना बोर्डों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, कार्यक्रम के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए आन-लाइन प्रबंधन निगरानी लेखाकंन प्रणाली (ओ एम एम ए एस) तथा तकनीकी लेखा-परीक्षा प्रणालियां भी बनाई हैं ।

ग्रामीण आवास

ग्रामीण आवास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इदिरा आवास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के वित्तीय संसाधनों में केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी 75: 25 के आधार पर है । 1985 में इसकी शुरूआत से अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए 1.54 करोड़ से अधिक आवासीय इकाईयां बनाई गई हैं ।

भारत - निर्माण के ग्रामीण आवास घटक के अन्तर्गत चार वर्षों में ग्रामीण गरीबों के लिए 60 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है । यह पैकेज देश में आवासहीनता को कम करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण आधारभूत सुविधा आधार को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिए बनाया गया है । 2005-06 के दौरान 14.4 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 15.5 लाख मकान बनाए गए थे जिस पर 3654 करोड़ रूपए खर्च हुए थे । जबकि 2006-07 के दौरान 15.3 लाख के लक्ष्य की तुलना में यह बताया गया कि 9.14 लाख से भी अधिक मकान बन चुके हैं जिस पर 2672 करोड़ रू0 खर्च हुए हैं तथा यह भी बताया गया है कि लगभग 9 लाख इकाईयां और बन रही हैं । इस प्रकार, विगत दो वर्षों के दौरान भारत - निर्माण के अंतर्गत 24 लाख से भी अधिक मकान बन चुके हैं ।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

भारत - निर्माण के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत कवर न की गई 55067 बसा वटों को 2009 तक स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है । इसके अलावा, ऐसी सभी बसावटों जो स्रोतों के खराब हो जाने के कारण पूर्ण कवरेज से आंशिक रूप से कवर की गई श्रेणी में आ गई तथा ऐसी बसावटों जहां जल गुणवत्ता की समस्याएं हैं, को भी कवर करने का प्रस्ताव है । भारत - निर्माण पैकेज के अंतर्गत 2005-06 तथा 2006-07 (नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार) के दौरान अब तक 163539 बसावटों और 112965 विद्यालयों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया गया है ।

2005-06 के दौरान कवर की गई 97215 बसावटों में 1536 कवर न की गई (एन सी) बसावटें, 11585 आंशिक रूप से कवर (पी सी) बसावटें, 79544 निचली श्रेणी में आ गई बसावटें तथा 4550 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें शामिल हैं । 2006-07 के दौरान अब तक कवर की गई 66324 बसावटों में 400 कवर न की गई (एन सी) बसावटें, 5171 आंशिक रूप से कवर (पी सी) की गई बसा वटें, 57939 निचली श्रेणी में आ गई बसावटें तथा 2814 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें शामिल हैं । 2005-

06 के दौरान कवर किए गए विद्यालयों की संख्या 72464 थी, जबकि 2006-07 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 40501 विद्यालयों को कवर कर लिए जाने की सूचना मिली है । स्वजलधारा तथा राट्रीय जल गुणवत्ता तथा मॉनिटरिंग एवं निगरानी कार्यक्रम पेयजल आपूर्ति योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं ।

ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में निवेश से ग्रामीण भारत में प्रगति की क्षमता बढ़ेगी । ग्रामीण ि वकास मंत्रालय सड़क संपर्क, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लक्ष्यों को निर्धारित समय के भीतर हासिल करके भारत निर्माण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं ।